



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 1974/पौष 17, 1895

No. 6] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 1974/PAUSA 17, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 7th January 1974

G.S.R. 8(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Northern Rice Zone (Movement Control) Order, 1968, namely:—

1. (1) This Order may be called the Northern Rice Zone (Movement Control) Second Amendment Order, 1973.

(2) It shall come into force at once.

2. In clause 3 of the Northern Rice Zone (Movement Control) Order, 1968, for sub-clause (1), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(1) No person shall export or attempt to export or abet the export of rice except under and in accordance with a permit issued by—

(a) the Central Government or by an officer authorised in that behalf by the Central Government; or

(b) the State Government concerned with the previous approval of the Central Government.”

[No. 204(GENL)(1)/71-PY.II/WT.IV]

ISHWAR CHANDRA, Jt. Secy.

कृषि संचालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1974

सा० का० नि० 8(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरी चावल जोन (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम उत्तरी चावल जोन (संचलन नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 1973 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. उत्तरी चावल जोन (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1968 के खण्ड 3 में, उपखण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

“(1) कोई व्यक्ति—

(क) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी या

(ख) केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से सम्बद्ध राज्य सरकार, द्वारा जारी किये गए परमीट के अधीन और अनुसार के सिवाय चावल का निर्यात नहीं करेगा या निर्यात करने का प्रयास या दुष्प्रेरण नहीं करेगा।”

[सं० 204(जी ई एन एल)(1) 71-पी वार्ड II/डब्ल्यू टी० 4]

ईश्वर चन्द्र, संयुक्त सचिव।